नंबर-वन हरियाणा

मुख्यमंत्री बनने के बाद सभी नेता अपनी विकास यात्रा का गुणगान करते हैं, चाहे वह भजनलाल हों या चौटाला, अपने शासन काल को सर्वश्रेष्ठ और जनहितकारी का दर्जा देते हैं। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा भला इसमें पीछे क्यों रहते? उन्होंने भी साढ़े तीन वर्ष के अपने शासन काल में हरियाणा को नम्बर वन राज्य घोषित कर दिया।

आज की राजनीति योजनाओं की घोषणाओं पर आधारित है। 1 नवम्बर, हरियाणा दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा का इश्तहार सभी अखबारों में छाया रहा।

उनकी घोषणाओं और योजनाओं पर एक नजर -

हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय सबसे ऊपर - जिस राज्य में आए दिन शिक्षित युवा रोजगार के लिए धरने और प्रदर्शन करते हों और उनपर लाठियां बरसाई जाती हों, मजदूर वर्ग को पूरी मजदूरी नहीं मिल पाती हो, आम जनता महंगाई की मार से जूझ रही हो, उस राज्य में प्रति व्यक्ति की आय क्या हो सकती है, आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। एक आदमी एक लाख रुपये महीने में कमाता है और एक भर पेट रोटी भी नहीं खा सकता। उनके बीच की इस खाई को कैसे पाटा जा सकता है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से जरूरी है उसका समान होना। अमीरी और गरीबी के बीच की दूरी को कम करना। औसत आय निकालकर प्रति व्यक्ति आय बढ़ा दिखाना सिर्फ छलावा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए 619.05 करोड़ रुपये खर्च किये गए-

हरियाणा में लगभग 800 गांव हैं। प्रत्येक गांव में विकास के लिए यह राशि बांट दी जाती तो एक गांव के हिस्से में 7737500 रुपये आते जिससे एक गांव का संपूर्ण विकास हो सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राज्य के कितने ही गांव आज भी बदहाल हैं। गांव के हर गली-मोहल्ले में कोई न कोई समस्या मुंह फैलाए खड़ी है। अब सवाल उठता है कि राज्य के सरकारी कोष से निकाली गई इतनी बड़ी राशि गई कहां?

98 आदर्श गांवों मे 425 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे-

राज्य भर के गांवों पर नजर दौड़ाने के बाद मुख्यमंत्री जी की दिव्य दृष्टि 98 गांवों पर केन्द्रित हो गई जिनको उन्होंने स्वर्ग नगरी बनाने का संकल्प लिया है। इसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है, क्योंकि एक गांव के हिस्से में इतनी बड़ी राशि आती है जिससे एक शहर का विकास किया जा सकता है- लगभग -43767346 रुपये। अब देखना यह है कि कितने पैसे गांवों के विकास पर लगते हैं और कितने नेताओं-अफ़सरों की तिजोरियों में जाते हैं।

राज्य की स्वच्छता के लिए 175 करोड़ रुपये खर्च और 11 हजार सफाई कर्मचारी नियुक्त किये जा रहे -

जहां पर कई-कई सौ करोड़ के घोटाले किये जाते हों, वहां के नेता, मंत्री, अफसरों और ठेकेदारों के लिए इतनी छोटी रकम हजम करना कोई बड़ी बात नहीं है। रही बात 11 हजार सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की, तो क्या पहले से कार्यरत सफाई कर्मचारी अपना काम भली-भांति कर रहे हैं। नहीं, कर्मचारियों की फौज बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है जब तक वे अपने काम और जिम्मेवारी के प्रति गंभीर नहीं होते।

डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए 800 डॉक्टरों की भर्ती की जायेगी-

हरियाणा में डॉक्टरों के 2200 पद हैं। फिलहाल 1300 डॉक्टर ही कार्यरत हैं जिनमें से मात्र 150 ही स्पेशलिस्ट हैं। सरकारी अस्पतालों के प्रति डॉक्टरों में अरुचि पैदा हो रही है। कितने ही डॉक्टर समय से पूर्व वी.आर.एस. लेकर निजी प्रैक्टिस करने में जुट जाते हैं अथवा प्राइवेट अस्पतालों में काम करने लगते हैं। 800 डॉक्टरों की भर्ती करने के बाद भी राज्य में डॉक्टरों की कमी की समस्या को हल नहीं किया जा सकता।

1600 करोड़ रुपये के बिजली के बिल और 7100 करोड़ रुपये के किसानों के ऋण माफ किये-

जो जितना बड़ा जमींदार है, उतना ही वह सरकार का कर्जदार है। सरकार उनसे कर्ज वसूल करने में नाकाम रही तो माफ करने का ड्रामा कर दिया। भोले-भाले किसान सरकार की इस नीति को समझने में नाकाम रहे। माफी की बात करके किसानों के साथ छल किया जा रहा है। किसी न किसी रूप में सरकार किसानों से भुगतान अवश्य कराएगी, इसमें कोई दो राय नहीं।

मुख्यमंत्री महोदय ने करोड़ों रुपये खर्च करने का दावा किया है। पैसा खर्च हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं। सवाल है, पैसा कहां खर्च हुआ है? राजीव गांधी ने भी कहा था कि जब विकास के नाम पर एक रुपया खर्च किया जाता है तो मौके पर 15 पैसा ही पहुंच पाता है, बाकी नेता, मंत्री, अफ़सरों और ठेकेदारों की तिजोरियों में चला जाता है। जाहिर है, मुख्यमंत्री द्वारा खर्च किया गया पैसा भी इसी अनुपात में बंट गया होगा, वरना मुख्यमंत्री जी को अखबार और टी.वी. चैनल पर विज्ञापन देने की जरूरत नहीं पड़ती।

■ चंद्र प्रकाश साथी

ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल

झोलाछाप डॉक्टरों और निजी अस्पताल संचालकों की पौ-बारह

फरीदाबाद (ग्रामीण संवाददाता) ग्रामीण स्वास्थ्य के नाम पर प्रति वर्ष करोड़ों रुपये खर्च किये जा रहे हैं। सरकार यह दावा करती है कि वह ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए कई योजनायें चला रही है, लेकिन वस्तुस्थिति क्या है, यह भी उन लोगों को भली-भांति मालूम है जो गांवों में रहते हैं और रोज-ब-रोज बीमारियों से जूझते हैं। जिले में चार से पांच गांवों के बीच प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की एक डिस्पेंसरी तथा पांच से सात डिस्पेंसरियों के ऊपर मुख्य प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की गई है।

छांयसा और दयालपुर की डिस्पेंसरियां आल इंडिया इंस्टीच्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, नयी दिल्ली से संबंधित है। इन डिस्पेंसरियों में एमबीबीएस कर चुके इंटर्नशिप करने वाले डॉक्टर आते हैं जिन्हें साल भर की इंटर्नशिप के दौरान तीन माह ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र में सेवा देनी पड़ती है। आल इंडिया इंस्टीच्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एक और डिस्पेंसरी खोलने वाला है। इन डिस्पेंसरियों से राज्य सरकार का कोई लेना-देना नहीं है। इनकी पूरी व्यवस्था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के जिम्मे है। उपरोक्त दो डिस्पेंसरियों को छोड़ कर बाकी अन्य डिस्पेंसरियां राज्य सरकार की ओर से संचालित हैं। प्रत्येक डिस्पेंसरी में सप्ताह में एक या दो दिन ही डॉक्टर आते हैं। बाकी दिनों में डिस्पेंसरियां या तो बंद रहती हैं या खुली रहती हैं तो वहां डॉक्टर नहीं होता।

गांवों के गरीब और असहाय लोग ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में इलाज के लिए आते हैं। प्रत्येक रोगी का एक कार्ड बनाया जाता है जिसकी फीस एक रुपया है। डॉक्टर मरीज को सस्ती एंटीबाइटिक दवाई दे देता है। महंगी दवायें बाहर से खरीदने के लिए लिख दी जाती हैं। सवाल है, जिसके लिए दो वक्त की रोटी की व्यवस्था करना मुश्किल हो, वह 500 रुपये की दवा कैसे खरीदेगा? ऐसी स्थिति में वह रोगी को सरकारी अस्पताल का रास्ता दिखा देते है। वहां उसकी जो दुर्दशा होती है उसे कहने की जरूरत नहीं है।

गांव के समर्थ लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की तरफ मुंह भी नहीं करते। वे निजी अस्पतालों और डॉक्टरों से इलाज करवाना ज्यादा सुरक्षित समझते हैं। पिछले दिनों डेंगू बुखार से काफी लोग प्रभावित हुए थे। डेंगू से पीड़ित किसी भी रोगी का इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नहीं किया गया।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रति ग्रामीणों की उदासीनता के अनेकों कारण हैं। इस संवाददता ने गांवो में जाकर लोगों से इन स्वास्थ्य केंद्रों के बारे में पूछा। कुछ लोगों का कहना है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रतिदिन नहीं खुलते। ज्यादातर उनके दरवाजे पर ताले लगे होते हैं। आंगन में गाय-भैंस चर रही होती है। सभी डॉक्टर और नर्स शहर में रहते हैं। वे प्रतिदिन स्वास्थ्य केंद्रों में आना मुनासिब नहीं समझते। इसकी जांच-पड़ताल करने वाला भी कोई नहीं है कि स्वास्थ्य केंद्र कैसे चल रहे हैं, चल भी रहे हैं या नहीं?

बल्लबगढ़ क्षेत्र में दयालपुर और छांयसा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। यहां पर लैब सुविधा भी कहने के लिए और कागजी तौर पर मौजूद है। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें मलेरिया बुखार तक की जांच के लिए शहर जाना पड़ता है या फिर निजी अस्पतालों में।

दयालपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत शाहपुर कला, भटपुरा चंदवाली, सोतई, नवादा आदि डिस्पेंसरियां हैं जिनमें सप्ताह में नियमवार डॉक्टरों का आना निर्धारित है।

छांयसा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत नरियाला, मोहमदपुर, गखेड़ा, पन्हेड़ा कला, फतेहपुर बिल्लौच, लढोली, बहवलपुर, जवां आदि गांव आते हैं।

लोगों का कहना है कि इन स्वास्थ्य केन्द्रों में उनकी किसी बीमारी का ढंग से इलाज नहीं होता। बुखार तक के रोगी को भी शहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। यहां तो केवल गर्भवती महिलाओं को टीके लगाए जाते हैं, गर्भनिरोधक दवाइयां वितरित की जाती हैं और पोलियो दिवस पर बच्चों को दवा पिलायी जाती है। इसके अलावा शायद ही किसी बीमारी का यहां इलाज हो पाता हो। यही कारण है कि लोग अब इन स्वास्थ्य केन्द्रों के चक्कर में ही नहीं पड़ते।

इससे गांवों में स्थित झोलाछाप डॉक्टरों और निजी अस्पताल मालिकों की की पौ-बारह हो रही है। चार-छः महीने किसी डॉक्टर के यहां इंजेक्शन लगाना सीख कर ये कुर्सी-मेज लेकर अपना क्लीनिक खोल कर बैठ जाते हैं। ये महज दसवीं-बारहवीं पास होते हैं।

खांसी, जुकाम, बुखार, कान बहना, चर्म रोग आदि का इलाज तसल्लीबख्श यहां किया जाता है। इस तरह के लिखे बोर्ड आपको इनकी दुकानों के बाहर लगे मिल जाएंगे। गांवों में न जाने कितनी मौतें इन झोलाछाप डॉक्टरों की वजह से होती हैं।

गांवों में स्थित कितने ही नर्सिंग होम बिना एमबीबीएस डॉक्टरों के चल रहे हैं। ज्यादातर इनके मालिक झोलाछाप डॉक्टर ही होते हैं। किसी प्रशिक्षित डॉक्टर का कागज दिखाकर इनको 10 बेड के नर्सिंग होम चलाने की अनुमति आसानी से मिल जाती है। स्वास्थ्य विभाग इन यम के दूतों पर कोई पाबंदी नहीं लगाता। हर कस्बे और गांवों में इस तरह के नर्सिंग होम खुलेआम चल रहे हैं, क्योंकि ये समय-समय पर स्वास्थ्य विभाग के अफसरों का मुंह मीठा कराते रहते हैं।

प्रति वर्ष जिस देश में लाखों लोग अकाल मृत्यु के शिकार हो जाते हैं, सामान्य बीमारियों में ही लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, कितने ही चिकित्सा के अभाव में राम के प्यारे हो जाते हैं, उस देश की स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी संतोषजनक है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।

प्रति वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन से ग्रामीण स्वास्थ्य के नाम पर लिया जाने वाला कर्ज आखिर जाता कहां है? क्या महज दिखावे के लिए गांव-गांव में स्वास्थ्य केन्द्र की शाखाएं खोली गई हैं? आज भी ग्रामीण समाज भीषण स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहा है। यह अकेले हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों की ही समस्या नहीं है बल्कि पूरे देश में यही दुर्दशा कायम है। बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा आदि राज्यों में पी.एच.सी. शाखाएं महज कागजों पर चल रही हैं।

ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था पर गत दिनों सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की, वह सरकार के मुंह पर एक करारा तमाचा है। लेकिन करोड़ों रुपयों का गबन करने वाले मंत्रियों और अफसरों पर इस तरह की टिप्पणियों का कोई असर नहीं होता।

प्रति वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन से ग्रामीण स्वास्थ्य के नाम पर लिया जाने वाला कर्ज आखिर जाता कहां है? क्या महज दिखावे के लिए गांव-गांव में स्वास्थ्य केन्द्र की शाखाएं खोली गई हैं? आज भी ग्रामीण समाज भीषण स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहा है। यह अकेले हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों की ही समस्या नहीं है बल्कि पूरे देश में यही दुर्दशा कायम है।

निवेदन : -

'मजदूर मोर्चा' एक अव्यावसायिक प्रकाशन है जो पूरी तरह पाठकों के सहयोग पर निर्भर है। सुधी पाठकों से निवेदन है कि वे 'मजदूर मोर्चा' को आर्थिक सहयोग प्रदान करें ताकि यह जनहित के मुद्दों को लगातार उठाता रहे। चंदे की दर निम्नलिखित है - वार्षिक सहयोग राशि - 50 रुपये मात्र

आजीवन सहयोग राशि - 500 रुपये मात्र

राशि निम्न पते पर भेजें - संपादक 'मजदूर मोर्चा' 1 डी/2 बी पी नियर हार्डवेयर चौक, एनआईटी, फरीदाबाद